

नवाभारत

विभाजन के बाद भारत आए लोग शरणार्थी नहीं, संघर्ष योद्धा- भागवत

पीएम के विश्वसनीय सलाहकार अमित शाह

जून में यूपीआई लेनदेन ने रफ्तार पकड़ी

अमेरिका की जीत बेल्जियम का कमबैक



भारत-जापान में बड़े समझौते

पीएम नरेंद्र मोदी ने जापान की पीएम ताकाइची को बताया छोटी बहन

नई दिल्ली, 02 जुलाई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची ने गुरुवार को भारत-जापान संबंधों को नई ऊंचाई देने के उद्देश्य से व्यापक द्विपक्षीय वार्ता की. संयुक्त प्रेस वक्तव्य में दोनों नेताओं ने आर्थिक, रणनीतिक, तकनीकी, ऊर्जा और निवेश सहयोग को और मजबूत बनाने की प्रतिबद्धता जताई.

प्रधानमंत्री मोदी ने सानाए ताकाइची की पहली भारत यात्रा का स्वागत करते हुए उन्हें अपनी छोटी बहन बताया और कहा कि जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री का भारत में स्वागत करना उनके लिए प्रसन्नता का विषय है. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक संयुक्त रोडमैप तैयार किया है. इसके अंतर्गत सेमीकंडक्टर, क्वांटम टेक्नोलॉजी, एडवांस्ड मैटेरियल्स और महत्वपूर्ण सप्लाय चेन को सुदृढ़ बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारी और आपसी भरोसा दोनों देशों की सबसे बड़ी ताकत है.



जापान के राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होंगे

संयुक्त प्रेस वार्ता में जापान की प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें अपनी सुंदर छोटी बहन कहा और दोनों नेताओं ने भाई-बहन जैसे आत्मीय संबंधों को आगे बढ़ाने की भावना व्यक्त की. उन्होंने कहा कि जापान की फ्री एंड ओपन इंडो-पैसिफिक (एफओआईपी) नीति और भारत की महासागर (एमएचएसएसजीएआर) पहल एक-दूसरे की पूरक हैं. इसी आधार पर दोनों देशों ने समुद्री सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने का निर्णय लिया है ताकि इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में शांति, स्थिरता और नियम-आधारित व्यवस्था को बढ़ावा मिल सके. ताकाइची ने कहा कि भारत और जापान एशिया की दो प्रमुख लोकतांत्रिक शक्तियां हैं और दोनों देश कानून आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था का समर्थन करते हैं. उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की धमकी, दबाव या बल प्रयोग के माध्यम से यथास्थिति बदलने के प्रयासों का दोनों देश मिलकर विरोध करेंगे. प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी बताया कि अगले वर्ष भारत और जापान के राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होंगे. इस अवसर पर दोनों देशों के बीच संस्कृति, पर्यटन, रचनात्मक अर्थव्यवस्था और जन-से-जन संपर्क को बढ़ावा देने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे.

भारत में 1000 बायोगैस व ऑर्गेनिक खाद संयंत्र लगाने पहल

इंडिया-जापान बायोगैस इनिशिएटिव के तहत भारत में 1000 बायोगैस और ऑर्गेनिक खाद संयंत्र स्थापित किए जाएंगे. इस पहल का उद्देश्य गोबरधन योजना को मजबूती देना, जैविक उर्वरक उत्पादन को बढ़ावा देना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और सतत विकास को प्रोत्साहित करना है. प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ऊर्जा सुरक्षा को साझा प्राथमिकता मानते हैं। इसी दिशा में दोनों देशों ने बेदरी प्रायोगिकी, ग्रीन हाइड्रोजन और न्यूक्लियर एनर्जी जैसे क्षेत्रों में

सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनाई है. इसके अलावा दोनों देशों ने इंडिया-जापान नेक्स्ट जेनरेशन मोबिलिटी पार्टनरशिप फ्रेमवर्क भी शुरू किया है, जिसका उद्देश्य भविष्य की परिवहन तकनीकों और औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देना है. उन्होंने कहा कि ऑटोमोबाइल क्षेत्र में भारत-जापान की सफल साझेदारी को अब जहाज निर्माण, एरिएशन और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित किया जाएगा। साथ ही कौशल विकास, तकनीकी प्रशिक्षण,

एक नजर में

दो विधानसभा सीटों पर उपचुनाव 30 जुलाई को

नई दिल्ली. चुनाव आयोग ने गुरुवार को बिहार, गुजरात विधानसभा की तीन रिक्त सीटों के लिए उपचुनाव 30 जुलाई को कराने की घोषणा की. इनमें बिहार की बांकीपुर और गुजरात की मंजलपुर सीट शामिल है. चुनाव आयोग की ओर से घोषित कार्यक्रम के अनुसार इन तीनों सीटों पर उपचुनाव के लिए अधिसूचना सोमवार छह जुलाई को जारी की जाएगी. नामांकन पत्र 13 जुलाई तक भरे जा सकेंगे और नामांकन पत्रों की जांच 14 जुलाई को की जाएगी।

अमेरिका ने इराक को भेजी डॉलर की नकद खेप

न्यूयॉर्क. अमेरिका ने कई महीनों की रोक के बाद इराक को डॉलर की नकद खेप भेजना आंशिक रूप से फिर से शुरू कर दिया है. इराक के प्रधानमंत्री के प्रवक्ता के हवाले से यह रिपोर्ट दी है. प्रधानमंत्री अली अल-जैदी के प्रवक्ता हैदर अल-अब्दी ने कहा, इराक को डॉलर की खेप भेजना दोबारा शुरू हो गया है और इस समस्या को सुलझा लिया गया है. इससे पहले, अमेरिकी हितों को लगातार नुकसान का हवाला देते हुए अमेरिका ने अप्रैल में सुरक्षा सहायता और तेल राजस्व से मिलने वाले नकद भुगतान पर रोक लगा दी थी.

नरोत्तम को चुनौती दे सकते हैं अनुज भारती

दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव का ऐलान

प्रशासनिक संवाददाता भोपाल, 2 जुलाई. प्रदेश की प्रतिष्ठित दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए चुनाव आयोग ने कार्यक्रम घोषित कर दिया है. यहां होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए 6 जुलाई को अधिसूचना जारी होगी, वहीं 30 जुलाई को मतदान होगा, चुनाव परिणाम 3 अगस्त को घोषित होंगे.

इधर उपचुनाव का कार्यक्रम घोषित होते ही प्रदेश में राजनीतिक सरगमी तेज हो गई है.



सामान्य तौर पर विधानसभा उपचुनाव में उम्मीदवारों के नामों को लेकर काफी अटकलें लगती हैं. लेकिन इस बार ऐसी स्थिति बनने की संभावना नहीं है. मिले संकेतों के मुताबिक भाजपा की ओर से एक बार फिर प्रदेश के

ऐसा रहेगा चुनावी कार्यक्रम

- ➡ 6 जुलाई - अधिसूचना जारी
- ➡ 13 जुलाई - नामांकन की अंतिम तिथि
- ➡ 14 जुलाई - नामांकन पत्रों की जांच
- ➡ 16 जुलाई - नाम वापस लेने की अंतिम तिथि
- ➡ 30 जुलाई - मतदान
- ➡ 3 अगस्त - मतगणना
- ➡ 4 अगस्त - चुनाव प्रक्रिया पूर्ण

कद्दावर नेता और पूर्व गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा चुनाव मैदान में उतर सकते हैं.

रूसी मिसाइल-ड्रोन हमले में आठ लोगों की मौत

कीव, 2 जुलाई. यूक्रेन की राजधानी कीव पर गुरुवार तड़के रूसी मिसाइल और ड्रोन हमलों में कम से कम आठ लोगों की मौत हो गई तथा 25 अन्य घायल हो गए.

कीव सैन्य प्रशासन के प्रमुख तिमुर तकाचेंको ने बताया कि हमले में कई आवासीय क्षेत्रों को निशाना बनाया गया और बच्चों सहित बड़ी संख्या में नागरिक हताहत हुए हैं. हमले के बाद शहर के कई इलाकों को खाली कराया गया. उन्होंने आरोप लगाया कि

रूसी सेना ने एक बार फिर जानबूझकर रिहायशी क्षेत्रों को निशाना बनाया है, जिससे भारी तबाही हुई है. कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है. अधिकारियों ने हमले में मृतकों और घायलों की संख्या बढ़ने की आशंका जतायी है. यह हमला ऐसे समय हुआ जब यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कुछ घंटे पहले ही चेतावनी दी थी कि रूस बड़े पैमाने पर हमला करने की तैयारी कर रहा है. हमले के दौरान कीव में वायु रक्षा प्रणालियां सक्रिय रहीं.

फीफा के जश्न में चार लोगों की मौत

14 लाख लोग सड़कों पर उतर आये जीत के बाद

44 वर्षीय एक व्यक्ति की फैलिफोनिया में भी मौत की सूचना है

मेक्सिको सिटी, 2 जुलाई. मेक्सिको की फीफा विश्व कप जीत के बाद राजधानी मेक्सिको सिटी में हुए जश्न के दौरान मरने वालों की संख्या बढ़कर चार हो गयी है. मेक्सिको सिटी के सार्वजनिक स्वास्थ्य सचिवालय ने बुधवार को यह जानकारी दी.

देश के कई राज्यों में हो रही है जोरदार बारिश

24 घंटों के दौरान मुंबई में 172 मिमी बारिश रिकॉर्ड हुई

15 फीट ऊंची लहरें आज उठने की वीएमसी ने दी चेतावनी

नई दिल्ली, 2 जुलाई. देश के विभिन्न हिस्सों में मानसून सक्रिय होने के साथ ही कई राज्यों में भारी बारिश का दौर जारी है. महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में



लगातार वर्षा के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है. मौसम विभाग ने कई क्षेत्रों के लिए रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी करते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील की है. महाराष्ट्र में

महानगरपालिका (बीएमसी) ने गुरुवार दोपहर समुद्र में लगभग 15 फीट ऊंची लहरें उठने की चेतावनी जारी करते हुए लोगों को समुद्र तटों से दूर रहने की सलाह दी है. तेज बारिश के बीच साकीनाका क्षेत्र में एक व्यक्ति की खुले मैनहोल में गिरने से मृत्यु हो गई. चर्चगेट क्षेत्र में एक पेड़ गिरने से कई वाहन क्षतिग्रस्त हुए, जबकि अंधेरी सबवे में जलभराव के कारण यातायात प्रभावित हुआ. नवी मुंबई में जलभराव के दौरान करंट फैलने की घटना भी सामने आई, जिसकी चपेट में दो छात्राएं आ गईं.

आरोपियों के मकानों पर बुलडोजर की कार्रवाई

अयोध्या, 2 जुलाई. अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा मामले की जांच में गुरुवार को महत्वपूर्ण गतिविधियां देखने को मिलीं. स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) दोपहर लगभग तीन बजे राम मंदिर परिसर पहुंची और मामले से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जांच शुरू की. इससे पहले एसआईटी 15 से 20 जून के बीच भी मंदिर परिसर में जांच कर चुकी है.

दूसरी ओर अयोध्या पुलिस ने भी सुबह 11 बजे मंदिर पहुंचकर लगभग दो घंटे तक जांच की और

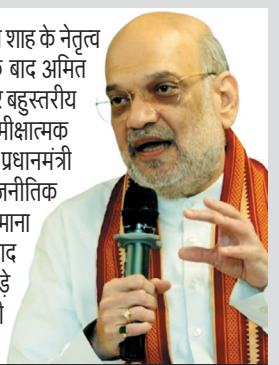
उस स्थान का निरीक्षण किया, जहां मंदिर में प्राप्त चढ़ावे की गिनती की जाती है. जांच के समानांतर शहर में विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला. सुबह 11.45 बजे 500 से अधिक अधिकवा सड़कों पर उतर आए और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट सदस्य अनिल मिश्रा तथा पूर्व पदाधिकारी गोपाल राव के खिलाफ प्रथमिकी दर्ज करने की मांग की. प्रदर्शन के बाद अधिकवाओं ने सिविल लाइन्स चौकी पहुंचकर तीनों सहित चार लोगों के विरुद्ध शिकायत पत्र भी सौंपा.

मंथन | अमित शाह के आवास पर बहुस्तरीय विमर्श

मंत्रिमंडल व संगठनात्मक विस्तार को लेकर चर्चा

प्रवेश कुमार मिश्र नई दिल्ली, 2 जुलाई.केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और संगठन महामंत्री बीएल संतोष की मौजूदगी में मंत्रिमंडल विस्तार व संगठनात्मक नियुक्तियों को लेकर महामंथन किया गया है. सूत्रों की माने तो लगभग ढाई घंटे तक चली इस बैठक के बाद यह तय हो गया है कि एक दो दिन के अंदर मंत्रिमंडल विस्तार और भाजपा अध्यक्ष की नई टीम की

जानकार बता रहे हैं कि जब भी अमित शाह के नेतृत्व में इस तरह की बैठक होती है उसके बाद अमित शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर बहुस्तरीय विमर्श के बारे में विस्तृत व समीक्षात्मक जानकारी देते हैं और उसके बाद प्रधानमंत्री अंतिम निर्णय कर लेते हैं. राजनीतिक गलियारों में इस बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसके तुरंत बाद सरकार और संगठन दोनों स्तरों पर बड़े नीतिगत और ढांचागत बदलावों की सुगुंवाहट तेज हो गई है.



घोषणा हो जाएगी. सूत्र बता रहे हैं कि इस महा-मंथन का मुख्य

संगठन में खाली पड़े प्रमुख पदों को भरना है. हाल के दिनों में भाजपा के कई वरिष्ठ मंत्रियों और कद्दावर नेताओं को राज्यों में महत्वपूर्ण संगठनात्मक जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, जिससे केंद्र और संगठन दोनों जगह कई अहम पद खाली हैं. आज की बैठक में इन पदों पर नए और युवा चेहरों को मौका देकर मिशन 2029 और आगामी राज्य विधानसभा चुनावों के लिए जमीन तैयार करने का ब्लूप्रिंट फाइनल किया गया है.

हाईकोर्ट ने वरिष्ठता आदेश निरस्त किए

जबलपुर. मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस विशाल धगट की एकलपीठ ने 10 वर्ष बाद विरिष्ठता सूची में बदलाव कर मुख्य चयन सूची के अधिकारियों से ऊपर प्रतीक्षा सूची के अधिकारी को स्थान देने के शासन के आदेश निरस्त कर दिए. कोर्ट ने कहा कि जिन अधिकारियों के सेवा अधिकार प्रभावित होते हैं, उन्हें सुनवाई का अवसर दिए बिना ऐसा निर्णय नहीं लिया जा सकता. अधिवक्ता अमित सिंह ने दलील दी कि यह मामला वर्ष 2008 की डिप्टी कलेक्टर भर्ती का है.

एआई से बने फर्जी फैसलों पर सुको सख्त

- बिना जांच एआई सामग्री पेश करना कदाचार
- दोषी वकीलों पर हो अनुशासनात्मक कार्रवाई

नई दिल्ली, 2 जुलाई. सुप्रीम कोर्ट ने अदालती कार्यवाही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के माध्यम से तैयार किए गए फर्जी और मनगढ़ंत न्यायिक फैसलों के इस्तेमाल पर कड़ा रुख अपनाते हुए इसे न्यायिक प्रक्रिया के लिए गंभीर चुनौती बताया है. अदालत ने स्पष्ट किया कि बिना जांच-पड़ताल के एआई से



तैयार सामग्री को कानूनी पिसाल के रूप में अदालत में पेश करना या उस पर भरोसा करना स्वीकार्य नहीं है. साथ ही बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) को इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश तैयार करने और अनुशासनात्मक कार्रवाई के नियम निर्धारित करने का निर्देश दिया गया है जस्टिस

पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ ने यह टिप्पणी एक्सेल इंफ्राप्रोजेक्ट्स से जुड़े दिवालियापन मामले की सुनवाई के दौरान की. मामले में राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) और राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) के आदेशों की समीक्षा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि एनसीएलटी ने अपने निर्णय में जिन न्यायिक मिसालों का उल्लेख किया था, उनमें कुछ फैसले वास्तविक रूप से अस्तित्व में ही नहीं थे, जबकि कुछ मामलों में वास्तविक फैसलों में मनगढ़ंत पैराग्राफ जोड़ दिए गए थे.